

प्रेषक,

मुख्य सचिव,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 01 फरवरी, 2008

विषय: शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" (Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation) का गठन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" (Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation) का गठन किये जाने का प्रस्ताव मा. मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 23.01.2008 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर सम्यक विचारोपरान्त मा. मंत्रिमण्डल के द्वारा प्रस्तावित निगम के गठन का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करते हुए निगम के गठन सम्बन्धी निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

1. राज्य के अन्तर्गत विविध अवस्थापना विकास के कार्यों के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाईवे आथोरिटी आफ इंडिया-एन0एच0ए0आई0) तथा उत्तर प्रदेश सेतु निगम आदि प्रतिष्ठित संस्थाओं की उपयोगी व्यवस्थाओं का अंगीकरण करते हुए "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" (Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation) नाम से राज्य के अपने एक स्वायत्तशासी निगम का गठन कर लिया जाय।
2. उक्त प्रस्तावित "उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम" (Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation) के गठन में निम्नवत् मूलभूत व्यवस्थाओं का प्राविधान किया जाय:-
 - 2.1 (i) प्रस्तावित निगम राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के अधीन गठित किया जायेगा तथा इसका मुख्यालय देहरादून में होगा। यह निगम भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होगा।
 - 2.1 (ii) इस निगम की अंशपूँजी शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निवेशित किया जायेगा।

2.1(iii) प्रस्तावित निगम के मुख्य उद्देश्य, जिनका समावेश निगम के Memorandum of Association में किया जायेगा, निम्न होंगे :-

(क) सभी प्रकार के भवनों, सेतु, राजमार्ग, मार्ग तथा अन्य अवस्थापना योजनाओं के निर्माण, निष्पादन, सम्पादन, विकास, प्रशासन, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा रख-रखाव के कार्य करना (To construct, execute, carryout, improve, work, develop, administer, manage, control or maintain all types of buildings, bridges, high ways, roads and other infrastructure projects.) ।

(ख) किसी भी प्रकार के अवस्थापना परियोजना यथा एक्सप्रेसवे, मार्ग, सेतु, भवन, रोपवे, टनल, पलाईओवर, एयरपोर्ट, नगर आदि के नियोजन, सम्पादन, विकास, प्रबन्धन, नियंत्रण एवं रख-रखाव तथा प्रभार आरोपण एवं वसूली सम्बन्धी कार्य स्वयं अथवा किसी कम्पनी, फर्म, सहकारी समिति अथवा व्यक्ति विशेष के माध्यम से पी.पी.पी. अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पादित करना (To plan, execute, carryout, improve, manage, control or maintain any infrastructure project e.g. expressways, roads, bridges, buildings, ropeways, tunnel, flyover, airports, townships etc. and levy, collect toll or award the infrastructure project on its own or through a company, firm, cooperative society, individual etc on the basis of a suitable public private partnership modality.) ।

(ग) निगम अथवा किसी अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की योजना तैयार करने, कियान्वयन प्रक्रिया में सहायता करने, प्रबन्धन करने अथवा गुणवत्ता के परीक्षण के निमित्त सम्बन्धित संस्था अथवा उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशानुसार सशुल्क अथवा निःशुल्क परीक्षण हेतु स्वतन्त्र विशेषज्ञों, कन्सलटेन्ट्स, अभियन्ताओं एवं प्रयोगशालाओं का एक पैनल बनाना (To maintain a panel of independent experts, consultants, engineers, laboratories etc. to plan, advice, execute, manage and examine quality of the work being carried by the Nigam or any other agency on the instruction of the said agency or the Government of Uttarakhand with or without the charges.

(घ) भारतवर्ष के अन्दर अथवा बाहर निर्माण सम्बन्धी सेवायें अथवा परामर्शी सेवायें सुलभ कराना (To develop and provide consultancy and construction services in India and abroad.) ।

2.2(i) निगम का नियमित संगठनात्मक ढांचा यथासंभव छोटा एवं अधिकारी आधारित रखा जायेगा जिसके अन्तर्गत निगम के मुख्यालय स्तर के साथ-साथ अत्यन्त न्यून संख्या में निर्माण इकाईयों के लिए तो नियमित पदों का प्राविधान करते हुए संविलियन/संविदा/

प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की व्यवस्था की जायेगी किन्तु क्षेत्रीय कार्यालयों/ईकाईयों की अवस्थिति एवं पदों की संख्या उपलब्ध कार्यभार की दृष्टि से परिवर्तनीय होंगे और इन पदों पर कार्मिकों की नवीन एवं नियमित तैनाती के बजाए पूर्णतः अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर कार्मिकों की व्यवस्था की जायेगी।

2.2(ii) निगम के कार्मिकों की व्यवस्था हेतु संविलियन/प्रतिनियुक्ति/संविदा के निमित्त राज्य सरकार के प्रशासकीय विभाग/निगमों के कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी और किन्हीं परिस्थितियों में यदि अपरिहार्य हुआ तो प्रदेश के बाहर की निर्माण एजेंसियों में कार्यरत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर अथवा खुले बाजार से संविदा पर कार्मिक लिए जाने पर भी विचार किया जायेगा।

2.2(iii) प्रस्तावित निगम के ढांचे के अन्तर्गत प्रारम्भ में मुख्यालय स्तर पर ढांचागत विकास करने के साथ-साथ 5 क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों की स्थापना की जायेगी जिनमें कार्मिकों/पदों की संख्या, उनके वेतन आदि पर संभावित व्यय निम्नवत् होगा:-

(क) मुख्यालय स्तर

क्र०सं	पद का नाम	संख्या	अनुमानित वार्षिक व्यय (रु० लाख में)
1	2	3	4
1	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1	10.00
2	निदेशक, परियोजना	1	8.00
3	निदेशक, नियोजन एवं पर्यवेक्षण	1	8.00
4	निदेशक, वित्त	1	8.00
5	निदेशक, पी.पी.पी.	1	8.00
6	निदेशक, आई.टी.	1	8.00
7	कम्पनी सचिव	1	6.00
8	महाप्रबन्धक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण	1	6.00
9	महाप्रबन्धक, सड़क एवं सेतु	1	6.00
10	महाप्रबन्धक, भवन	1	6.00
11	लेखाधिकारी	2	6.00
12	विधि अधिकारी	1	4.00
13	लेखाकार	3	4.50
14	आशुलिपिक	12	18.50
15	वरिष्ठ लिपिक	3	4.00
16	लिपिक	6	4.00
17	चपरासी/डाक रनर	16	10.00
	कुल	53	125.00

टिप्पणी: मुख्यालय पर कुल 53 कार्मिक होंगे जिन पर लगभग रु० 125.00 लाख वार्षिक व्यय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय सुविधाओं पर भी लगभग रु० 50.00 लाख प्रारम्भिक पूंजीगत व्यय होगा।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना इकाई स्तर

क0सं0	पद का नाम	संख्या	अनुमानित वार्षिक व्यय (रु0 लाख में)
1	2	3	4
1	परियोजना प्रबन्धक	1	5.00
2	आवासीय अभियन्ता	4	12.00
3	कनिष्ठ अभियन्ता	12.	18.00
4	लेखाकार	1	1.50
5	सह लेखाकार	1	1.25
6	प्रारूपकार/अनुरेखक	1	1.50
7	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	1	1.50
8	आशुलिपिक कम कम्प्यूटर आपरेटर	1	1.50
9	स्टोरकीपर	1	1.50
10	चपरासी	2	1.25
	कुल (प्रति इकाई)	25	45.00

टिप्पणी : उक्त प्रकार के प्रारम्भ में कुल 5 कार्यालय होंगे जिनसे सम्बन्धित 125 कार्मिकों पर लगभग रु0 225.00 लाख वार्षिक व्यय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रु0 50.00 लाख का प्रारम्भिक पूंजीगत व्यय भी होगा।

- 2.2(iv) प्रस्तावित निगम के कार्मिकों के वेतन एवं विविध व्ययों की व्यवस्था निगम को प्राप्त होने वाले सेन्टेज से की जायेगी।
- 2.2(v) विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु आउट-सोर्सिंग व्यवस्था पर बल दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय नियंत्रण एवं कार्य के निष्पादन के लिए तो विभागीय तन्त्र विकसित किया जायेगा तथा अन्य सेवायें यथा, माडल कन्सट्रक्शन एग्रीमेन्ट, डी.पी.आर. गठन, वास्तुविद् एवं डिजायन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार, गैर तकनीकी कार्यों (यथा, कम्प्यूटर आपरेटर, अनुसेवक, चौकीदार, वाहन चालक (वाहन सहित), स्वच्छकार आदि सेवाएँ) को भी यथासम्भव आउट-सोर्स किया जायेगा।
- 2.2(vi) अवस्थापना विकास के बृहद कार्यों हेतु वित्तीय व्यवस्था के निमित्त राज्य सरकार पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जायेगा और इस दृष्टि से 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मोड' को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 2.2(vii) प्रस्तावित निगम के द्वारा राज्य के अन्तर्गत विद्यालय भवन, पंचायत घर, पुलिस थाना/चौकी, विकास खण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, विभिन्न श्रेणी के चिकित्सालयों आदि सामान्य (कामन) श्रेणी के भवनों के माडल ड्राईंग एवं आगणन (राज्य की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक) तैयार किया जायेगा।

(5)

2.2(viii) कार्यो की निविदा आमंत्रित करने, गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयबद्ध भुगतान के सम्बन्ध में एक अत्यन्त स्वच्छ, पारदर्शी, समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली प्राविधानित/विकसित की जायेगी।

अतएव, कृपया मा. मंत्रिमण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये अनुमोदन/दिशा-निर्देश के आलोक में प्रस्तावित निगम के सम्बन्ध में मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराते हुए निगम के पंजीकरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।